

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एम. एल. चौहान, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 46 / 2017 (उदयपुर आर्डर)

श्रीमती सीता देवी पत्नी खेमराज जी दर्जी, निवासी पूजानगर झाडोल,
 तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
 काश्तकारी अधिनियम-1955 विरुद्ध
 आदे 1 उपखण्ड अधिकारी, झाडोल
 प्रकरण क्रमांक-2 प () राजस्व/
 2014 / 456 दिनांक 25-02-2014

----/----

उपस्थित(वक्तबहस) 1- श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्त
 2- श्री कमले 1 चौहान राजकीय अभिभाषक

----::----

निर्णय

दिनांक 14-12-2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार झाडोल के प्रस्ताव पर अपने आदे 1 दिनांक 25-02-2014 से ग्राम झाडोल की आराजी नंबर 626 रकबा 2.7335 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2993 रकबा 0.13 हैक्टर भूमि ग्राम पंचायत झाडोल को आबादी में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की, जिससे रूश्ट होकर अपीलान्त द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13-07-2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमले 1 चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।



अपीलान्ट ने अपील के साक्ष धारा 5 का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा तथाकथित आदे 1 उन्हें बिना सूचना दिये एवं बिना सुने पारित किया गया है, जिससे उक्त आदे 1 की जानकारी उन्हें नहीं हो सकी। दिनांक 05-07-2017 को कुछ लोग रास्ते की तरफ निर्माण कार्य करने लगे तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई देरी नहीं की गयी है। अतः दिनांक 25-02-2014 से 05-07-2017 तक की समयावधि को कण्डोन किया जावे। तार्ड में भापथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त आवेदन पर की गयी बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 25-02-2014 की अपील इस न्यायालय में 60 दिवस में अर्थात् दिनांक 24-04-2014 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु अपील दिनांक 13-07-2017 को अर्थात् करीब 3¼ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं एवं न ही इतनी लम्बी अवधि के लिए पर्याप्त कारण है। तदनुसार अपील मात्र मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा आदे 1 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा.दी. का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ कुछ दस्तावेज प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। तार्ड में भापथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त दस्तावेजों का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रस्तुत दस्तावेजात रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां हैं। अतः न्यायहित में इन्हें रेकार्ड पर लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा धारा 96 जा.दी. का भी आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं बताया कि कथित जमीन में आम रास्ते की जमीन को भामिल करते हुए रूपान्तरण किया गया है। अगर पंचायत द्वारा आबादी भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया गया तो प्रार्थी अपने जमीन पर नहीं आ जा सकेगा। इस कारण प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति होने से उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा प्रदान की जावे।

हमने उक्त आवेदन पर मनन कर पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 में विवादित आराजी नंबर 626 रकबा 2.7335 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2993 रकबा 0.13 हैक्टर

बिलानाम काबिल का त दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदे 1 से उक्त आराजी नंबर 626 रकबा 2.7335 हैक्टर में से 0.40 हैक्टर एवं आराजी नंबर 2993 रकबा 0.13 हैक्टर को ग्राम पंचायत झाडोल को आबादी विस्तार हेतु आबादी में रूपान्तरित किया है, जिससे हम अपीलान्त को किसी प्रकार से हितबद्ध एवं प्रभावित पक्षकार नहीं पाते हैं।

जहां तक गुणावगुण का प्र न है, विद्वान वकील अपीलान्त का मुख्य उजर यह है कि रूपान्तरित आराजियात से वह अपनी खातेदारी के खेतों पर आता जाता है, किन्तु राजस्व रेकार्ड में भूमि बिलानाम गैर काबिल का त दर्ज है, जिसमें रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि अपीलान्त के पास अपने खेतों पर आने-जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तो इसके लिए अपीलान्त को रास्ते हेतु अलग से चाराजोही करनी चाहिए थी, किन्तु बिलानाम गैर काबिल का त की भूमि का जो आबादी रूपान्तरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम पंचायत झाडोल के नाम किया गया है, उसमें हम प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्त बेरून मयाद होने, अपीलान्त हितबद्ध पक्षकार नहीं होने एवं गुणावगुण के आधार पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25-02-2014 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 14-12-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर